



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]

तई विल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 1980/आस्विन 5, 1902

No. 187] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 1980/ASVINA 5, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न हो जाती हैं जिसमें कि वह अलग संकलन की रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, स्थाय और कल्यानी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

संकलन

तई विल्ली, 26 सितम्बर, 1980

सं. का० 6(19) 80/-आई-सी० :—मरकार की यह नीति है कि संविधान के अनुच्छेद 39-क द्वारा जैसी परिकल्पना की गई है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आधिक या किसी अन्य नियोगिता के कारण कोई भागीरक न्याय प्राप्त करने के अवसर से बचित न रह जाए, नि.शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध की जाए।

सभी राज्यों और संघ राज्य भौद्रों में एकरूप आधार पर उपयुक्त और गतिशील विधिक सहायता कार्यक्रम स्थापित करने की दृष्टि से एक व्यापक और गत्यारक विधिक सेवा कार्यक्रम स्थापित करने से संबंधित सभी प्रश्नों को समीक्षा करने और उसके लिए उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए मई, 1976 में एक समिति गठित की गई थी (जिसे इसमें आगे भगवती समिति कहा गया है) जिसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती और मरकार मरकार मन्त्रालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री बी० आर० हुण अध्यक्ष थे।

भगवती समिति ने प्रथमी रिपोर्ट में विभिन्न सिफारिशें करने के पश्चात् यह महमूल किया कि व्यापक विधिक सहायता कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए अनेक अध्ययन करने होंगे और यह कि विधिक सहायता कार्यक्रमों का एक उपयुक्त विकास तैयार करने के लिए ज्ञान की अनेक शाखाओं में ममत्य स्थापित करना होगा;

ऐसे अध्ययनों और यमन्वय के प्रयोग के लिए स्थापित अन्तर विभागीय समिति ने भगवती समिति की रिपोर्ट में की गई ऐसी सिफारिशों की समीक्षा का कार्य पूर्ण कर लिया है,

अनेक राज्यों ने स्वयं प्रपनी प्रेरणा से विधिक सहायता कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिए हैं,

मरकार इस ज्ञान के लिए उत्सुक है कि देश में व्यापक विधिक सहायता स्कीम अधिनियम तैयार और लियान्वित की जाए,

बता केन्द्रीय मरकार इसके द्वारा विधिक सहायता स्कीम के लियान्वयन समिति नामक एक समिति गठित करती है।

2. इस समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(1) न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती	व्यापक
(2) न्यायमूर्ति श्री एम० आर० शर्मा, न्यायाधीश पंजाब	सदस्य
और हरियाणा उच्च न्यायालय।	
(3) नवाच (व्यय) विभाग मंत्रालय, भारत सरकार	मदस्य
(4) श्री मुकुल गंग चौधरी, ज्येष्ठ अधिकारी, कलकत्ता	मदस्य
(5) प्रो० एन० आर० साधू मेनत, विधि सकाद विली	सदस्य
विश्वविद्यालय।	
(6) श्रीमती विमला नारी, समाज सेविका, विली	सदस्य

3. इस समिति के हृत्य निम्नलिखित होंगे

- (1) भिन्न-भिन्न राज्यों में विभिन्न विधिक सहायता स्कीमों के कार्यकरण का ध्यान में रखकर, आपके विधिक महायता स्कीमों को विस्तृत रूप में तैयार करना और उन्हें क्रियान्वित करना।
- (2) राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में विधिक सहायता और सलाह की स्कीम को यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से मानीटर करना कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने के एक साधन के रूप में उनका कार्य प्रभावी रूप से चले।
- (3) ऐसी कार्रवाई करना या उनकी सिफारिश करना जो विधिक सहायता स्कीमों के उचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।
- (4) विधिक सहायता से संबंधित ऐसे विषयों पर जो केन्द्रीय विधि, न्याय और कल्पनी कार्य मंत्री उसे समय-समय पर निर्दिष्ट करे, विचार करना और उनके संबंध में रिपोर्ट देना या उनके बारे में आवश्यक कार्रवाई करना।

4. समिति का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और उनकी बैठक दिल्ली में या देश के ऐसे प्राय स्थानों पर जो समिति ठीक समझे उतनी बार होगी जितनी बार आवश्यक समझी जाए।

5. समिति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सबूद में अपने कार्य के प्रयोजन के लिए उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से एक या अधिक व्यक्तियों को सदस्य या सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकेगा।

6. समिति अपनी प्रक्रिया स्वयं तैयार करेगी। जहाँ अध्यक्ष मित्र-भूमिता के लिए या समिति के किसी कार्य को शीघ्र निपटाने के लिए या किसी अन्य कारण से ऐसा करना आवश्यक समझते हैं वहाँ वह या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत समिति का कोई अन्य सदस्य एकल रूप से कार्य करते हुए, समिति कि किसी कार्य को कर सकेगा।

7. समिति का गठन प्रथम तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया है और यह अपनी प्रथम रिपोर्ट अपनी प्रथम प्रथम बैठक से छह मास की अवधि के भीतर दियी जाए।

आवेदन

प्रारंभ दिया जाता है कि इस मकल्य की प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी विभागों और विभागों, राज्य सरकारों और संघ सामिति क्षेत्रों प्रशासनों आदि का भेजी जाए।

यह भी आवेदन दिया जाता है कि इस सकल्य को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पी०वी० वक्तासुब्रह्मण्यम्, मन्त्रिक

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Department of Legal Affairs)

RESOLUTION

New Delhi, the 26th September, 1980

No.F.6(19)/80—JC.—Whereas it is the policy of Government to provide free legal aid to ensure, as envisaged by article 39A of the Constitution, that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities;

And whereas with a view to establishing an adequate and vigorous legal aid programme on an uniform basis in all the States and Union Territories, a Committee (hereinafter referred to as the Bhagwati Committee), consisting of Shri Justice P. N. Bhagwati, Judge of the Supreme Court, as Chairman and Shri Justice V R. Krishna Iyer, Judge of the Supreme Court, as Member, was constituted in May, 1976 to examine all questions and make appropriate recommendations for establishing and operating a comprehensive and dynamic legal services programme;

And whereas the Bhagwati Committee, after making various recommendations in their Report, felt that many studies would have to be undertaken for formulating comprehensive legal aid programmes and that many departments of knowledge would have to be co-ordinated for drawing up a suitable picture of legal aid programmes;

And whereas an inter-departmental committee set up for the purposes of such studies and co-ordination has completed its examination of the recommendations made in the report of the Bhagwati Committee;

And whereas several States have already embarked upon legal aid programmes on their own,

And whereas Government is anxious that comprehensive legal aid schemes should be formulated and implemented in the country without delay,

Now, therefore, the Central Government hereby constitutes a Committee, to be known as the Committee for Implementing Legal Aid Schemes.

2. The Committee shall consist of.—

- (1) Justice P. N. Bhagwati
Judge of the Supreme Court of India —Chairman
- (2) Justice M. R. Sharma
Judge of the Punjab & Haryana High Court —Member
- (3) Secretary (Expenditure)
Ministry of Finance, Govt. of India —Member
- (4) Shri Subroto Roy Chowdhry
Senior Advocate, Calcutta —Member
- (5) Prof. N. R. Madhava Menon
Faculty of Law, Delhi University —Member
- (6) Smt. Vimla Nagi
Social Worker, Delhi —Member

3. The functions of the Committee shall be the following.—

- (1) to formulate in detail and to implement comprehensive legal aid schemes after taking into account the working of the various legal aid schemes in different States;
- (2) to monitor the scheme for legal aid and advice in the States and Union Territories with a view to ensuring their effective functioning as a means of securing social justice;
- (3) to take or recommend such other steps as are necessary to secure proper working of the legal aid schemes;
- (4) to consider and report on, or take necessary action with respect to, such matters pertaining to legal aid as the Union Minister of Law, Justice and Company Affairs may refer to it from time to time;

4. The Committee will have its headquarters at Delhi and may meet as often as considered necessary at Delhi or at such other places in the country as the Committee may deem fit.

5. The Committee may for the purpose of its work with respect to any State or Union Territory co-opt. one or more persons as Members or Member from that State or Union Territory.

6. The Committee shall evolve its own procedure. Where the Chairman considers it necessary so to do in the interest of economy or for the expeditious disposal of any business of the Committee or for any other reason, he, or any other Member of the Committee authorised by him in writing in this behalf, may, acting singly, attend to any work of the Committee.

7. The Committee is constituted for three years in the first instance and shall submit its first report within a period of six months from the date of its first meeting.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all Ministries and Departments of the Government of India, State Governments and Union Territory Administrations, etc.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. B. VENKATASUBRAMANIAN, Secy.

